बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 33 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 11 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

सीबीआई ने 2.4 लाख रुपये रिश्वत लेते पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक को एक संपत्ति की सत्यापन रिपोर्ट देने के लिए कथित तौर पर 2.4 लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। ज्योति नगर पुलिस थाने में तैनात एएसआई पाटिल कुमार ने दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में लंबित एक मामले में एक संपत्ति के बारे में अनुकूल सत्यापन रिपोर्ट जमा करने के लिए शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। अधिकारियों ने बताया कि कुमार ने कथित तौर पर धमकी दी थी कि अगर रिश्वत नहीं दी गई, तो वह शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट पेश कर देंगे।

क्लाउड सीडिंग से पैसा बर्बाद! डॉक्टरों की चेतावनी- अब तो बचों के फेफड़े भी काले, विशेषज्ञों की राय- दिल्ली से भाग जाओ...

नई दिल्ली।

दिल्ली की हवा इन दिनों जहर से भरी है। हर सांस के साथ लोगों के फेफड़ों में प्रदूषण उतर रहा है। ऐसे में उम्मीद थी कि क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश से इस धुंध को धोने में मदद मिलेगी, लेकिन अब इस प्रयोग की समयसिद्धता और वैज्ञानिक तर्क पर ही सवाल उठने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही साफ चेतावनी दी थी कि दिल्ली के आसमान में न तो बादल हैं, न नमी – यानी बारिश की संभावना लगभग शून्य थी। इसके बावजूद भी इस महंगे प्रयोग को अंजाम दिया गया।

जलवायु विशेषज्ञ मंजरी शर्मा के अनुसार, यह पूरा प्रयास वैज्ञानिक दृष्टि से गलत समय पर किया गया प्रयोग था। उन्होंने कहा कि भारत मौसम विभाग ने पहले ही आईआईटी दिल्ली को स्पष्ट कर दिया था कि वायुमंडल में नमी बेहद कम है और क्लाउड सीडिंग की सफलता के लिए कम से कम 60-70 प्रतिशत नमी जरूरी होती है।

अस्थायी राहत, भारी खर्च

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि मान लीजिए यह प्रयोग सफल भी होता, तो भी इसका असर महज दो से ढाई दिन तक ही रहता। प्रदूषण फिर से लौट आता – यानी लगातार क्लाउड सीडिंग करनी पड़ती, जिसका खर्च हर बार करोड़ों में होता। अनुमान है कि अगर पूरी सर्दियों में यह प्रक्रिया जारी रखी जाए, तो 25 से 30 करोड़ रुपये तक का खर्च आएगा।

न बादल, न नमी – क्यों नहीं बरसी बारिश

दिल्ली-एनसीआर की हवा में इस समय नमी का स्तर बेहद कम है। आसमान साफ है और हवा में धूलकणों की मात्रा बहुत अधिक। ऐसे में बारिश कराने की तकनीक असफल होना तय था। क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट बताती है कि क्लाउड सीडिंग तभी सफल हो सकती है जब पर्याप्त बादल मौजूद हों, लेकिन इस

समय वायुमंडल सूखा था, इसलिए पूरा प्रयोग व्यर्थ साबित हुआ।

डॉक्टरों की चेतावनी – अब तो बचों के फेफड़े भी काले

दिल्ली की जहरीली हवा सिर्फ प्रयोगों की नाकामी नहीं दिखा रही, बल्कि मानव शरीर के भीतर तबाही की तस्वीर भी पेश कर रही है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि पिछले 30 वर्षों में उन्होंने मरीजों के फेफड़ों में डरावना बदलाव देखा है। पहले के मरीजों के फेफड़े हल्के गुलाबी होते थे, जो स्वच्छ हवा में सांस लेने वालों के निशान होते हैं। आज वही फेफड़े पूरी तरह परमानेंट काले हो चुके हैं – धूल, कालिख और जहरीले कणों से भरे हुए। डॉ. कुमार का कहना है कि पहले यह स्थिति सिर्फ धूम्रपान करने वालों या फैक्ट्री कर्मचारियों में दिखती थी, लेकिन अब बचों और महिलाओं के फेफड़े भी कोयले जैसे काले दिखने लगे हैं।

विशेषज्ञों की राय — बारिश नहीं, नीति चाहिए

मंजरी शर्मा का कहना है कि दिल्ली में सिर्फ कृत्रिम बारिश या सड़कों पर पानी छिड़कने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को क्लीन एयर की मांग करनी चाहिए, न कि क्लाउड सीडिंग जैसी अस्थायी राहत पर निर्भर रहना चाहिए। अगर संभव हो तो इस जहरीली हवा से बचने के लिए दिल्ली से दूर जाना ही बेहतर है। वायु प्रदूषण अब केवल सांस लेने में तकलीफ की समस्या नहीं रह गया है – यह धीरे-धीरे मौत की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषित हवा से जुड़ी बीमारियों के कारण मौतों का प्रतिशत चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है।

आंकड़ों के अनुसार –

36फीसदी मौतें स्ट्रोक के कारण होती हैं, जो प्रदूषित हवा से मस्तिष्क पर पड़ने वाले असर का नतीजा है।

33फीसदी मौतें फेफड़ों के कैंसर से जुड़ी हैं, जो लंबे समय तक धूल, धुआं और जहरीले कणों के संपर्क में रहने से होता है।

31फीसदी लोग हृदय रोग के शिकार होकर जान गंवाते हैं।

20फीसदी मौतें क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी फेफड़ों की बीमारियों से होती हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के प्रदूषित इलाकों में अब बचों और युवाओं के फेफड़े भी तेजी से कमजोर हो रहे हैं। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण न केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एनीमिया और मल्टी-सिस्टम ऑर्गन फेलियर जैसी स्थितियां भी पैदा कर सकते हैं।

डॉक्टरों की चेतावनी

गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल के फेफड़ा विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण अब धीरे-धीरे हर अंग पर असर डाल रहा है – हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, किडनी और यहां तक कि नसों की कार्यप्रणाली भी इसकी चपेट में आ रही है।

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम का नया अवतार, दिल्ली में बनेगी आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी

नई दिल्ली । युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक नया खेल शहर विकसित किया जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कतर इस परियोजना के लिए प्रमुख संदर्भ होंगे। भारतीय खेल मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने इन देशों का दौरा किया था ताकि उनके खेल बुनियादी ढांचे का अध्ययन किया जा सके और JLN खेल शहर के विकास के लिए जानकारी एकत्र की जा सके। भारत ने लंदन में राष्ट्रमंडल खेल मूल्यांकन समिति के समक्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए अपना प्रस्ताव औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया है। भारत ने 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भी आधिकारिक तौर पर बोली लगाई है। अध्यक्ष उषा के नेतृत्व में IOA ने अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को एक आशय पत्र प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का निर्माण 1982 में 9वें एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए किया गया था और बाद में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए इसे नवीनतम अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का रखरखाव और उपयोग वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है, जो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकसित करने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं और योजनाओं को लागू करने की विरासत का हिस्सा है। नई दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भारत के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्टेडियमों में से एक है। यह कई महत्वपूर्ण खेल आयोजनों का गवाह रहा है।

हाल ही में, जेएलएन स्टेडियम ने पिछले महीने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की, जिसमें 100 से अधिक देशों के 2,200 से अधिक प्रतिभागियों ने 186 पदक स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा की। पहली बार मेजबान के रूप में, उन्होंने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य सहित रिकॉर्ड 22 पदक जीते, जो अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी करके, भारत ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया है जो आमतौर पर कुलीन और प्रतिष्ठित आयोजकों के लिए आरक्षित है। प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी, जिसमें पैरा एथलेटिक्स को एक पदक प्रतियोगिता के रूप में शामिल किया गया था। हालाँकि, कई अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीटों, विश्व चैंपियनों और भारतीय खेल दिग्गजों के अनुसार, इस WPAC ने किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेज़बानी करने की भारत की क्षमता को एक अलग स्तर पर पहुँचा दिया है।

पीएम-सीएम और मंत्रियों को पद से हटाने वाले संशोधन बिल पर जल्द बनेगी जेपीसी : लोकसभा अध्यक्ष

नई दिल्ली । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कोहिमा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है। बता दें, यह विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर अपराध के मामले में 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान करता है। उन्होंने आगे कहा कि संसदीय समितियों को राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि इन समितियों में ऐसे विषयों पर चर्चा होती है जो राजनीतिक सीमाओं से परे हैं।

उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों का इसमें प्रतिनिधित्व हो। उन्होंने यह भी जोड़ा कि समिति का गठन शीघ्र किया जाएगा ताकि विधेयक पर व्यापक चर्चा हो सके। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे कई विपक्षी दलों ने इस जेपीसी का हिस्सा बनने से इनकार किया है। वहीं, एनसीपी-एसपी ने अन्य विपक्षी दलों से अलग रुख अपनाते हुए समिति में शामिल होने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) भी इसमें शामिल होने की तैयारी में है। यह समिति कुल 31 सदस्यों वाली होगी।

विधेयक को लेकर विवाद और तर्क

यह संविधान संशोधन विधेयक और दो अन्य प्रस्तावित विधेयक संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन, 20 अगस्त को पेश किए गए थे। इसके बाद लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर इन विधेयकों को संयुक्त समिति के पास भेजने का निर्णय लिया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह विधेयक कानून के उस बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करता है जिसके तहत व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसका अपराध साबित न हो। उनका तर्क है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को केवल गिरफ्तारी या जमानत न मिलने के आधार पर स्वचालित रूप से पद से हटाना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है।

इस मामले में सरकार का तर्क है कि यह कानून आवश्यक है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करने के लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान जरूरी है। बिरला ने कहा कि समितियां मिनी संसद की तरह होती हैं जहां विभिन्न दलों के सदस्य निष्पक्ष रूप से विषयों पर चर्चा करते हैं। वे कोहिमा में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के भारत क्षेत्र जोन-III के 22वें वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने पहुंचे थे। वहीं, आगे उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में योजनाबद्ध व्यवधान लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं मानी जा सकती। उन्होंने कहा कि संसद जनता के मुद्दे उठाने और सार्थक बहस के लिए सर्वोत्तम मंच है, इसलिए राजनीतिक दलों को इसका रचनात्मक उपयोग करना चाहिए। बिरला ने कहा कि सभी दलों से चर्चा कर सत्र को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाएगा।

1 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र

शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 15 बैठकें होंगी। विपक्ष ने सत्र की छोटी अवधि पर सरकार को घेरा है। बिड़ला ने स्पष्ट किया कि सत्र की अवधि तय करना सरकार का विशेषाधिकार है और यह उसके विधायी एजेंडे पर निर्भर करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी दल जनता से जुड़े मुद्दे सदन के भीतर उठाएंगे, न कि बाहर।

जेलें नहीं 7-सितारा होटल! बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त

नई दिल्ली । बेंगलुरु जेल के वायरल वीडियो विवाद के बीच, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर तीखा हमला बोला। पूनावाला ने कर्नाटक की जेलों में भ्रष्टाचार और मिलीभगत को उजागर किया, जो अपराधियों के लिए पार्टी ज़ोन बन गई हैं। पूनावाला ने एएनआई को बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस के शासन में, कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, और भ्रष्टाचार और मिलीभगत इतनी बढ़ गई है कि कर्नाटक की जेलें अब पार्टी ज़ोन बन गई हैं। भाजपा नेता ने दावा किया कि वायरल वीडियो में, एक बलात्कार के दोषी, एक आईएसआईएस भर्तीकर्ता और एक सोने के तस्कर के पास बेंगलुरु की जेल में टेलीविजन और मोबाइल फोन की सुविधा है। पूनावाला ने कहा कि जेल से जिस बेशर्मी से कुछ वीडियो सामने आए हैं, उन्हें देखिए। इसमें हम एक सजायाफ्ता सीरियल रेपिस्ट को देख सकते हैं, जिसने कर्नाटक में कई महिलाओं को प्रताड़ित किया है, उसके पास फ़ोन और टेलीविज़न की सुविधा है। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में शामिल एक आईएसआईएस भर्तीकर्ता, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है, के पास मोबाइल फ़ोन की सुविधा है। देश को भारी नुकसान पहुँचाने वाले एक सोने के तस्कर के पास शराब, पार्टियाँ और मोबाइल फ़ोन की सुविधा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार अपराधियों का समर्थन करती है और दावा करती है कि वे जेल में सात सितारा होटलों जैसी सुविधाओं का आनंद लेते हैं। पूनावाला ने इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृह मंत्री जी. परमेश्वर से जवाबदेही की माँग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन और राय का संरक्षण इन खूंखार अपराधियों को दिया गया है, जो जेल के अंदर सात सितारा सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं... यह व्यवस्था में व्याप्त पूर्ण भ्रष्टाचार है और केवल बयानबाजी और आक्रोश पर्याप्त नहीं है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की जवाबदेही होनी चाहिए। उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्हें आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बीच, भाजपा ने इस घटना के विरोध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेंगलुरु स्थित सरकारी आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा जिला प्रभारी एस. हरीश ने बेंगलुरु जेल के अंदर कुख्यात अपराधियों और आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनाने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, इस कांग्रेस सरकार में जेल अब जेल नहीं रही... वे एक सुरक्षित पनाहगाह बन गई है... देश भर के आतंकवादी बेंगलुरु जेल में स्थानांतरित होना चाहते हैं क्योंकि यह एक सुरक्षित पनाहगाह बन गई है... वे केवल इसी जेल को चाहते हैं...। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परेश्वरप्पा के तत्काल इस्तीफे की मांग की है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेने को कहा है।

हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है..., किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नकली वीडियो बनाए जाने की जानकारी है. चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा है कि उन्होंने और उनके साथी जज जस्टिस विनोद चंद्रन ने अपने बारे में भी बने फर्जी वीडियो को देखा है. कोर्ट में यह चर्चा उस याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई जिसमें न्यायपालिका में एआई के उपयोग को लेकर उचित नियम बनाए जाने की मांग की गई है. माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस अपनी तरफ जूता फेंके जाने के नकली वीडियो के बारे में ऐसा कह रहे थे. ध्यान रहे कि 6 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 11:35 बजे एक वकील ने अपना जूता मुख्य न्यायाधीश की तरफ फेंका था, जो उन तक नहीं पहुंचा. इस घटना का कोई स्पष्ट वीडियो नहीं था, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर एक फर्जी वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें जूता चीफ जस्टिस के बगल से गुजरता हुआ दिखा. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को 2 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए लगाने को कहा है. इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे चीफ जस्टिस गवई ने संकेत दिया कि वह इस मामले को नहीं सुनना चाहते. उन्होंने याचिकाकर्ता कार्तिकेय रावल के लिए पेश वकील से पूछा, आप क्या चाहते हैं. मैं याचिका खारिज कर दूं या इसे 2 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए लगाया जाए? याचिका में कहा गया है कि अब अदालतें खुद भी एआई का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन यह उपयोग सकारात्मक कार्यों के लिए हो रहा है. कोर्ट को एआई के खतरों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए. जनरेटिव एआई उपलब्ध आंकड़ों की खुद समीक्षा कर निष्कर्ष निकालता है. इस तकनीक से गलत या भ्रामक जानकारी मिलने का अंदेशा है. इसके जरिए उपलब्ध जानकारी में पारदर्शिता का अभाव है और यह पक्षपात से भरी हो सकती है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कोर्ट एआई तकनीक के इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश तय करे ताकि न्यायिक प्रक्रिया में गलत या भ्रामक एआई सामग्री का असर न पड़े. याचिका में यह भी कहा गया है कि अदालती कार्यवाही के मॉर्फ किए गए वीडियो न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जनता में गलत धारणा पैदा कर सकते हैं.

बदल रही है पूर्वोत्तर की सियासत

अनिल जैन

देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी के छोटे भाई और एक समय सरकार के चहेते कारोबारी रहे अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन मुश्किलें बढ़ने के बाद यह भी सवाल है कि उन्हें इतनी रियायतें क्यों मिल रही हैं? उनके खिलाफ जितने मामले हैं और उनमें जिस तरह की कार्रवाई की खबरें आ रही हैं, उन्हें देखते हुए उनकी गिरफ्तारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ऐसे मामलों में आमतौर पर केंद्रीय एजेंसियां गिरफ्तारी पहले करती हैं और बाकी कार्रवाई उसके बाद होती है। लेकिन अनिल अंबानी पर सारी कार्रवाई हो रही है, मगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। खबर है कि ईडी ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों की तीन हजार करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। इससे पहले खबर आई थी कि उनके बेटे जय अनमोल पर भी वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। उससे पहले खबर आई थी कि देश के दो बड़े बैंकों ने अनिल अंबानी की कंपनी के एकाउंट को फ्रॉड घोषित किया है। उन पर 17 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं लेकिन उनसे टुकड़ों-टुकड़ों में पूछताछ हो रही है। इसीलिए सवाल है कि आगे क्या होगा? इसी तरह धीमी गति से मामला चलता रहेगा या सचमुच कोई कार्रवाई होगी या फिर मामला अनिश्चित-अनिश्चित ठंडे बस्ते में चला जाएगा? गौरतलब है कि अनिल अंबानी ही वह पहले शख्स थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कामना की थी।

कोयला घोटाले में भी कोई दोषी नहीं

डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की बदनामी और 2014 में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की सबसे बड़ी वजह दो कथित घोटाले बने थे। पहले 2जी स्पेक्ट्रम वाली दूरसंचार घोटाला और फिर कोयला घोटाला सामने आया। कहा गया कि दूरसंचार घोटाला एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का है और उसके बाद सामने आया कोयला घोटाला तीन लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया गया। सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस बुरी तरह हार गई और भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई। इसी हवा में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी बन गई। लेकिन अब एक-एक करके इन दोनों घोटालों के आरोपी बरी हो रहे हैं। दूरसंचार घोटाले के मुख्य आरोपी तत्कालीन संचार मंत्री ए.राजा सहित सब बरी हो गए। काफी समय के बाद सीबीआई ने अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी। हालांकि उसमें यह लगभग तय है कि किसी को कुछ नहीं होने वाला है। अब कोयला घोटाले में एक-एक करके सारे लोग बरी हो गए हैं। तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता पहले एक मामले में बरी हुए थे और अब छत्तीसगढ़ कोयला खदान से जुड़े मामले में भी बरी हो गए हैं। उनके साथ-साथ दूसरे अधिकारी और कारोबारी भी बरी हुए हैं। घोटाले की आरोपी एक कंपनी के मालिक नवीन जिंदल बहुत पहले ही भाजपा में शामिल हो गए। इन घोटालों का यह हश्र होने कारण ही अब भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा नहीं बन रहा है, जबकि बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं।

पूर्वोत्तर में बदल रही है राजनीति

भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाने के बाद पूर्वोत्तर पर राजनीतिक रूप से बहुत ध्यान दिया। पूर्वोत्तर के छोटे एनडीए का एक नया समूह नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेडा बनाया, जिसका जिम्मा हिमंत बिस्वा सरमा को दिया गया। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद नेडा अप्रभावी होता गया। पहले जहां भाजपा ने दो राज्यों को छोड़ कर सब जगह अपनी या सहयोगी पार्टियों की सरकार बना ली थी, अब वहां सरकार और राजनीति दोनों उसके हाथ से निकल रही है। उसकी सहयोगी पार्टियां उसको छोड़ कर अलग रास्ता पकड़ रही हैं। पिछले दिनों नगालैंड में सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) ने नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) में विलय फैसला किया। नई पार्टी का नाम एनपीएफ होगा और इसके नेता मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो होंगे। 60 सदस्यों की विधानसभा में इस नई पार्टी के 34 विधायक हो गए हैं। पार्टी बहुमत के लिए उसे अब भाजपा के 12 विधायकों की जरूरत नहीं है। इसी बीच नया घटनाक्रम यह है कि मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के नेता कोनराड संगमा ने त्रिपुरा में भाजपा की सहयोगी टिपरा मोथा पार्टी से हाथ मिला लिया है। दिल्ली में एनपीपी के नेता और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और टिपरा मोथा के नेता प्रद्योत देबबर्मन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। दोनों पार्टियां पूरे पूर्वोत्तर में साझा राजनीति करेंगी। अपने क्षेत्र को मणिपुर की छठी अनुसूची में बना कर रखने के साथ-साथ अस्मिता की राजनीति के लिहाज से पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा से दूरी बना रही है।

कांग्रेस में थरूर के दिन पूरे हुए

लगता है शशि थरूर ने मान लिया है कि अब कांग्रेस में उनके दिन पूरे हो गए हैं। अभी तक वे नीतिगत मसलों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखते हुए वंशवाद का मुद्दा उठा दिया है। थरूर ने कहा है कि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। केरल की तिरुवनंतपुरम से चार बार के सांसद शशि थरूर इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार के कारण यह विचार भारत की राजनीति में स्थापित हुआ कि राजनीतिक नेतृत्व जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है। इस तरह से उन्होंने देश की सभी प्रादेशिक पार्टियों में चल रही वंशवादी राजनीति के लिए भी नेहरू-गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। शशि थरूर ने 'प्रोजेक्ट सिंडिकेट' की ओर से 31 अक्टूबर को प्रकाशित लेख में यह भी कहा है कि दशकों से एक परिवार राजनीति के शीर्ष पर बना हुआ है। इससे पहले थरूर जो कुछ कह या कर रहे थे, उसकी कांग्रेस में माफी थी लेकिन शायद इसकी माफी नहीं है कि उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार को निशाना बनाया, वंशवाद पर सवाल उठाया और देश में वंशवादी राजनीति की जड़ें मजबूत करने में सोनिया और राहुल गांधी के परिवार का हाथ बताया। थरूर के लिए यह निर्णायक क्षण है। अब बिहार चुनाव खत्म होने वाला है और भाजपा का फोकस केरल पर बनेगा। थरूर उसमें अपनी भूमिका देख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो तिरुवनंतपुरम सीट पर विधानसभा के साथ उपचुनाव हो सकता है।

कायम है केजरीवाल का बंगला मोह!

अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बंगले के विवाद में फंसे हैं। इस बार मामला चंडीगढ़ में कथित तौर पर मिले एक बंगले का है। असल में उन्होंने सस्ती नीली कमीज और वैगन आर गाड़ी से अपनी जो छवि बनाई थी वह पिछले चुनाव में पूरी तरह से खत्म हो गई, जब कथित तौर पर उन्होंने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके अपने लिए बंगला बनवाया। इस बंगले ने केजरीवाल की सारी पुण्याई खत्म कर दी। लेकिन सवाल है कि क्या उन्होंने इससे कोई सबक लिया? ऐसा लगता नहीं है। उल्टे ऐसा लग रहा है कि बंगला उनकी दुखती नस बन गया है। अभी वे फिरोजशाह रोड पर अपनी पार्टी के सांसद और कारोबारी अशोक मित्तल को मिले बंगले में रह रहे हैं। उनकी पार्टी ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ कर उनके लिए एक बंगला आवंटित कराया है। राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख के नाते उन्हें लोधी इस्टेट में 95 नंबर बंगला आवंटित हुआ है। हालांकि इसमें भी उन्हें आपत्ति है कि टाइप आठ का बंगला क्यों नहीं मिला। अभी जो बंगला मिला वह टाइप सात का है। उस बंगले में रेनोवेशन के बाद केजरीवाल रहने जाएंगे।

इस बीच एक और बंगले का विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में दो एकड़ का एक बंगला मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस के लिए आवंटित किया है, जिसमें केजरीवाल रहते हैं। वह कोई नया बंगला नहीं है लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक केजरीवाल का बंगला मोह नहीं छूट रहा है।

सम्पादकीय...

मदर ऑफ डेमोक्रेसी!

यारब न विरोधी समझे हैं न समझेंगे मोदी जी की बात! बताइए, मोदी जी के विरोधी ब्राजील की मॉडल को हरियाणा की मतदाता सूची में एंट्री तक का स्वागत करने को तैयार नहीं हैं। उल्टे इसके वोट चोरी का सबूत होने का शोर मचा रहे हैं। मोदी जी की इच्छा से ज्ञानेश बाबू अगर मतदाता सूची को अंतर्राष्ट्रीय बनाने में लगे हुए हैं, उसमें सिर्फ एक प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के और सिर्फ अपने देश के ही नहीं, परदेश के भी लोगों के भी चेहरे लाने में लगे हुए हैं, तो किसलिए? जाहिर है कि भारत की डेमोक्रेसी को इंटरनेशनल बनाने के लिए। आखिर, हमारी डेमोक्रेसी, मदर आफ डेमोक्रेसी है या नहीं? पर सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने से ही क्या होगा? दुनिया से मनवाना भी तो पड़ेगा कि डेमोक्रेसी की मम्मी हमारे पास है। वर्ना जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? और दुनिया हमारे कहने से ही थोड़े ही मान लेगी हमारे पास डेमोक्रेसी की मम्मी है। दुनिया सबूत मांगेगी। और अब हम भी उसके मुंह पर सबूत दे मारने की स्थिति में होंगे। हमारी मतदाता सूची में ब्राजीलियाई मॉडल का नाम है और वह भी एक बार नहीं, बार-बार, पूरे बाईस बार! और किसी देश में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मतदाता सूची होगी क्या? और सुनते हैं कि ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर के साथ, दर्जनों वोट पड़े भी थे। यानी हरियाणा में डेमोक्रेसी को ब्राजीलियाई मॉडल ने जमकर सहारा दिया है। होने को तो दुनिया में डेमोक्रेसी में और बहुत कुछ भी है, बहुत सी वैराइटी है। अमरीका के ट्रंप और तुर्किए के एर्दुआ जैसे कहने को चुनाव से बने राष्ट्रपति हैं, जो खुद को पुराने जमाने के बादशाहों से कम नहीं समझते हैं। पड़ोस में पाकिस्तान जैसे और आगे बांग्लादेश में होने जा रहे चुनाव हैं, जिनमें चुनाव तो होता है, लेकिन विपक्ष नहीं होता है। और तो और नेतन्याहू जैसे नेता भी हैं, जो नेता तो चुनाव से बने हैं, पर ऐसे चुनाव में जिसमें जिस आबादी पर राज कर रहे हैं, उसके बड़े हिस्से को वोट देने का अधिकार ही नहीं है। ऐसी-ऐसी ढीली डेमोक्रेसी भी हैं, जहां नागरिक को वोट देने का मौका मिलता है, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। और भी बहुत कुछ। पर मतदाता सूची के ऐसे अंतर्राष्ट्रीयकरण की हमारे जैसी दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। फिर भी हमारी मतदाता सूचियों में ही मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लक्षण और भी बहुतेरे हैं। सुना है कि हरियाणा में तो मतदाता सूची में एक माताजी के फोटो के साथ पूरे 222 वोट पाए गए हैं। लाखों वोटर हैं, जिनका पता संख्या वाला शून्य है या अक्षरों में शून्य है यानी अ, ब, स, द वगैरह। हजारों वोटर, छोटे-छोटे घरों में सैकड़ों की तादाद में, मुर्गियों की तरह भी नहीं, शायद कबूतरों की तरह रहते हैं। हजारों वोटर हैं, जिन्हें एक व्यक्ति एक वोटर की कैद मंजूर नहीं है और एक व्यक्ति, अनेक वोटर बनकर रहने की आजादी पसंद करते हैं, आदि, आदि। बेशक, ये सब भी हैं तो डेमोक्रेसी की मम्मी वाले लक्षण ही। फिर भी जो वजन ब्राजीलियाई मॉडल को भारतीय जनतंत्र का महत्वपूर्ण सहारा बनाने में है, वह दूसरे छोटे-मोटे लक्षणों में कहां है! लेकिन, कोई इससे यह नहीं समझे कि हमारा मदर ऑफ डेमोक्रेसी का दावा सिर्फ अनोखी मतदाता सूचियों पर ही टिका हुआ है। हर्गिज नहीं। वैसे हमारी मतदाता सूचियों का अनोखापन भी सिर्फ किसी ब्राजीलियाई मॉडल का मोहताज नहीं है। बेशक, मोदी जी की ही इच्छा से, ज्ञानेश गुप्ता जी के विशेष शुद्धिकरण की गंगा में नहाकर निकली मतदाता सूचियां तो अपने आप में एक अजूबा हैं। देखा नहीं कैसे बिहार में एक-दो नहीं, दस-बीस नहीं, सैकड़ों नहीं, दसियों हजार लोग जब पहले चरण में गांव-मोहल्ले के नजदीक के मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि मतदाता सूचियों को तो उनके नाम से ही शुद्ध कर दिया गया है। जाहिर है कि गरीब-गुरबा की गंदगी जितनी कम होगी, सूचो उतनी ही ज्यादा स्वच्छ होंगी। मतदाता सूचियों की जो सफाई कराने की बीस साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई, वह सफाई मोदी-ज्ञानेश की जोड़ी करा रही है और ऐरों-गैरों से मतदाता सूची को स्वच्छ करा रही है। लेकिन, स्वच्छता लाने का मतलब सिर्फ कूड़ा-कर्कट हटाना ही थोड़े ही है। स्वच्छता का मतलब मतदाता सूचियों में सलमा-सितारे टांकना भी है। जुगल जोड़ी ने सूचियों में सितारे भी खूब ही टांके हैं। तभी तो मोदी जी की पार्टी के पूर्व सांसद, पहले संसद के चुनाव में और फिर इसी साल के शुरू में विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में वोट डालने के बाद, साल खत्म होने से पहले ही बिहार में वोट डाल आए। और सिर्फ पूर्व सांसद जी ही थोड़े ही, मोदी जी की पार्टी के दूसरे कई नेता, दिल्ली के बाद बिहार में वोट डाल आए। और उत्तराखंड समेत दूसरे कई राज्यों के नेता भी। और ये तो वो नेता हैं जो ढोल पीटकर, राय बदल-बदलकर वोट डालते देखे गए। जो सैकड़ों किसी ब्राजीलियाई मॉडल या किसी बुजुर्ग दादी की फोटो के पीछे छुपकर वोट डाल आए होंगे, उनका क्या? ऐसे टूरिस्ट वोटर भी दुनिया में और कहां मिलेंगे? दुनिया क्या अब भी हमें डेमोक्रेसी की मदर नहीं मानेगी! वैसे डेमोक्रेसी की मदर होने के साक्ष्य और भी बहुत हैं। हमारे जैसा तटस्थता-युक्त चुनाव आयोग दुनिया में कहां और होगा, क्या? विशेष ट्रेनों में भर-भरकर, दूसरे राज्यों से मतदाताओं को जैसे मोदी-शाह पार्टी बिहार के चुनाव के लिए लायी है, वैसे दुनिया में और कहीं लाने दिया जाता होगा क्या? सरायरंजन में वीवीपैट की हजारों पर्चियां जैसे खेतों में पड़ी मिली हैं, वैसे वीवीपैट वाली मशीन से कहीं और चुनाव कराया जाता होगा क्या? जैसे यहां-वहां ईवीएम के स्ट्रांग रूमों में बिजली जाने और सीसीटीवी बंद होने और संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायतें आयी हैं, उस सब के बाद भी चुनाव आयोग कान में तेल डालकर कहीं और सोया रहता होगा क्या? दुनियावालो, मोदी जी-ज्ञानेश जी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलवाने के लिए, अब और क्या करना होगा?

बिहार में वीवीपैट पर्चियां !

भारत के संविधान निर्माता चुनावी काल में चुनाव आयोग को ऐसी असीमित शक्तियां देकर गये हैं कि लोकतन्त्र में हर स्तर पर लोक (जनता) तन्त्र पर प्रभावी रहे। चूंकि लोकतन्त्र का अर्थ लोगों का तन्त्र होता है अतः तन्त्र कभी भी लोगों पर भारी नहीं पड़ना चाहिए। यदि लोकतन्त्र में तन्त्र लोगों पर भारी पड़ने लगेगा तो प्रजातन्त्र की व्यवस्था के सुचारू चलने की उम्मीद क्षीण होती जायेगी। इस मामले में चुनाव आयोग भारत में लोकतन्त्र स्थापित करने वाले संस्थानों में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है क्योंकि यही लोगों के तन्त्र की आधारशिला रखता है। भारत के राजनीतिक शासनतन्त्र को ही लोकतन्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम जनता राजनीतिक दलों की मार्फत ही अपना तन्त्र स्थापित करने की इच्छा जताती है। भारत ने आजाद होने के बाद संसदीय प्रणाली का लोकतन्त्र अपनाया। इस तन्त्र में बहुमत का शासन तो होता है मगर अल्पमत में आये राजनीतिक दलों को भी सत्ता में अपनी भागीदारी इस प्रकार निभानी पड़ती है कि कभी भी बहुमत के नशे में चूर होकर कोई भी राजनीतिक दल मनमानी न कर सके और संविधान की सीमा में रहे। लोकतन्त्र में भागीदारी का नमूना संसदीय लोकतन्त्र की मार्फत ही सफल हो सकता है क्योंकि सत्ता पक्ष का चुनाव भी जनता करती है और विपक्ष का चुनाव भी यही करती है। इन सब तथ्यों के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका बहुत संजीदा हो जाती है इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को सरकार का हिस्सा नहीं बनाया और इसे स्वतन्त्र व स्वायत्त संस्थान का दर्जा दिया। चुनाव आयोग को हमारे संविधान निर्माताओं ने सीधे लोक (लोगों) के प्रति जवाबदेह बनाया और इसे सीधे संविधान से शक्ति लेकर अपना कार्य करने में सक्षम बनाया। चुनाव आयोग को वह संवैधानिक जिम्मेदारी तय की गई कि वह सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के समय एक जैसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा जिससे उसकी निगाह में पहले से ही सत्तारूढ़ दल और अन्य दलों के बीच किसी प्रकार का अन्तर न रहे। चुनाव के समय चुनाव आयोग को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कौन सा दल हुकूमत में है और कौन सा विपक्ष में। उसके समक्ष सभी राजनीतिक दल एक समान होते हैं। संविधान के अनुसार जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो उस प्रदेश की शासन व्यवस्था चुनाव आयोग के नियन्त्रण में आ जाती है। बेशक पहले से स्थापित सरकार हुकूमत पर काबिज रहती है मगर उसके सभी मन्त्री आदि अपने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ही हो जाते हैं। यह नियम राष्ट्रीय चुनावों के समय भी रहता है। चुनाव के समय कोई मन्त्री या मुख्यमन्त्री से लेकर प्रधानमन्त्री तक चुनाव प्रचार करते हैं तो वे अपनी पार्टी के खर्चे पर ही चुनाव प्रचार करते हैं। बेशक उनकी सुरक्षा आदि में जुड़े शिष्टाचार का पालन किया जाता है मगर उनके मन्त्री होने का असर चुनाव आयोग पर नहीं रहता। आजकल बिहार में चुनाव चल रहा है जिसके पहले चरण का मतदान विगत 6 नवम्बर को हो चुका है और दूसरे व अन्तिम चरण का मतदान आगामी 11 नवम्बर को होना है। मतदान से वोटों की गणना होने तक के समय के भीतर मतपेटियों या ईवीएम मशीनों की सुरक्षा की गारंटी देना चुनाव आयोग का ही काम होता है। यह गारंटी परोक्ष रूप से भारत के संविधान द्वारा ही चुनाव आयोग के माध्यम से दी जाती है परन्तु बिहार में विगत 6 नवम्बर को हुए मतदान की ईवीएम मशीनों में लगी वीवीपैट मशीनों की रसीदी पर्चियां सड़कों पर पड़ी मिलती हैं तो इसकी सीधी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर ही जाती है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ रहा है। बिहार से ईवीएम मशीनों के रखरखाव को लेकर जिस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग भारी गफलत में है और वह अपने कारिन्दों की मार्फत मशीनों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इस स्थित को लेकर यदि विपक्षी दल आग-बबूला हो रहे हैं तो यह जायज ही माना जायेगा। अतः चुनाव आयोग को इस बाबत तुरन्त स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि ईवीएम मशीनों में जनता की वह इच्छा कैद है जिसे जनादेश कहा जाता है और लोकतन्त्र जनादेश से ही चलता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान समय आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का समय है जिसमें मशीनों की सुरक्षा के लिए कैमरे हर समय मौजूद रहते हैं। चुनाव के बाद मशीनों को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे स्ट्रांगरूम या वज्रगृह कहा जाता है जहां मतगणना होने तक 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है। अब वह समय नहीं रहा कि बैलेट पेपरों से भरे कनस्तर मतगणना के बाद कहीं कूड़े के ढेर में पड़े हुए मिलते थे। 1974 में जब उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए थे तो उस समय राज्य के मुख्यमन्त्री स्व. हेमवती नन्दन बहुगुणा थे। इन चुनावों में विपक्षी संगठन कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमन्त्री स्व. चन्द्रभानु गुप्ता ने लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से चुनाव लड़ा था और वह इन्दिरा गांधी की नई कांग्रेस के प्रत्याशी से चुनाव हार गये थे। मगर परिणाम आने के बाद सरोजिनी नगर के एक इलाके से ही बैलेट पत्रों से भरे कनस्तर बरामद हुए थे। ऐसे मामले राज्य में एक-दो स्थानों पर और भी हुए थे लेकिन अब सीसीटीवी का जमाना है जो हर गतिविधि को कैमरे में कैद कर लेता है। ऐसे हालात में यदि बिहार के समस्तीपुर जिले की सरायरंजन विधानसभा सीट के एक इलाके में ईवीएम मशीनों से जुड़ी वीवीपैट की पर्चियां हजारों की संख्या में मिलती हैं तो चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है? ये पर्चियां क्षेत्र के शीतलपट्टी गांव में हजारों की संख्या में मिली जिनसे बच्चे खेल रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर जिले के कलैक्टर व पुलिस कप्तान मौके पर पहुंचते हैं और जिलाधीश दो कर्मियों को निलम्बित कर देते हैं। मगर क्या इससे चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा बहाल हो सकती है? सरायरंजन से जद (यू) के श्री विजय चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं जो कि मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। इस सरायरंजन सीट पर 6 नवम्बर को 73 प्रतिशत से भी अधिक मतदान हुआ। लोगों ने अपने अधिकार का जमकर उपयोग किया और लोकतन्त्र के झंडे को फहराया मगर क्या उनकी मेहनत सड़क किनारे पड़ी मिली पर्चियों में बेकार ही चली जायेगी। असली सवाल यही है जिसका उत्तर चुनाव आयोग को देना है।

'नक्शा' आपकी भूमि की डिजिटल पहचान

जब भारत एक समावेशी और विकसित भविष्य की कल्पना करता है, तो इसका सबसे मजबूत आधार-स्तंभ भूमि है। चाहे घर हो, खेत हो, दुकान हो या स्मार्ट सिटी का सपना हो- विकास का प्रत्येक रूप भूमि पर अवस्थित होता है। हालांकि, सच्चाई यह है कि वर्षों से हमारे भू-अभिलेख अधूरे, भ्रामक और अक्सर विवादों में उलझे रहे हैं। परिणामस्वरूप, आम नागरिकों को संपत्ति खरीदने, जमीन विरासत में प्राप्त करने, ऋण प्राप्त करने या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग ने नक्शा (राष्ट्रीय शहरी निवास-स्थल भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण) कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह भारत में भूमि प्रबंधन, प्रशासन और भूमि-रिकॉर्ड रख-रखाव में बदलाव लाने की एक पहल है। यह कार्यक्रम एक पारदर्शी, डिजिटल और सत्यापित भू-अभिलेख प्रणाली का निर्माण कर रहा है, जो न केवल नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगी, बल्कि कस्बों और शहरों के विकास को भी गति प्रदान करेगी। भारत में, भूमि पंजीकरण लंबे समय से एक जटिल व दस्तावेज-आधारित प्रक्रिया रही है। बिक्री विलेख, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, पटवारी सत्यापन और तहसील स्तर पर प्रस्तुतिया ये सभी नागरिकों के लिए पूरी प्रणाली को बोझिल बना देती थीं। पुराने रजिस्टर और फाइलों में न केवल त्रुटियां मौजूद थीं, यही कारण है कि लाखों भारतीयों के लिए, सुरक्षा के स्रोत के रूप में भूमि का महत्व कम होता गया और यह जोखिम का प्रमुख स्रोत बन गई। नक्शा कार्यक्रम, सटीक और डिजिटल भू-रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण, जीएनएसएस मानचित्रण और जीआईएस उपकरण जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाता है। इस पहल के तहत, नागरिकों को 'सोरबो' (शहरी संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड) कार्ड मिलता है, जो स्वामित्व का एक डिजिटल प्रमाण है और संपत्ति के लेन-देन को आसान बनाता है। सरकार 'सोरबो' कार्यक्रम को समर्थन दे रही है। नक्शा के साथ, लोगों को अब स्वामित्व की पुष्टि के लिए दस्तावेजों या बिचौलियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। नागरिक आसानी से ऑनलाइन प्रारूप मानचित्र देख सकते हैं और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। यह डिजिटल प्रणाली कराधान को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाती है। नक्शा कार्यक्रम का प्रभाव व्यक्तिगत स्वामित्व और प्रशासनिक दक्षता से कहीं आगे तक फैला हुआ है और यह आपदा प्रबंधन और शहरी नीति-निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रहा है। सत्यापित डिजिटल स्वामित्व रिकॉर्ड यह भी सुनिश्चित करते हैं कि मुआवजा और सहायता सही लाभार्थियों तक शीघ्रता से पहुंचे। इससे आपदा के बाद,पुनर्स्थिति को बहाल करने की प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है। इसके अलावा, नक्शा संतुलित और सतत अवसंरचना विकास को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक शहरी सुदृढ़ता का समर्थन करता है।

क्या वास्तव में बैंक निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है?-वित्त मंत्री के बयानों से उत्पन्न हलचल

वैश्विक स्तरपर भारत में बैंकिंग क्षेत्र हमेशा से आर्थिक नीति और सामाजिक न्याय का केंद्र रहा है। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ जिस नए युग की शुरुआत हुई, उसका उद्देश्य केवल पूंजी का पुनर्वितरण नहीं था बल्कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को वित्तीय समावेशन में लाना था।बैंक शाखाओं का ग्रामीण विस्तार,प्राथमिक क्षेत्र को ऋण प्रवाह,और आम नागरिक की आर्थिक पहुंच को सुनिश्चित करना,ये सब उस नीति का सार था। परंतु अब, जब भारत की अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण और प्रतिस्पर्धा की नई लहर में प्रवेश कर चुकी है,तो सवाल उठता है,क्या राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी सामाजिक भूमिका के साथ-साथ आर्थिक दक्षता भी निभा पा रहे हैं? इसी संदर्भ में हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान ने न केवल नीति निर्माताओं,बल्कि बैंक यूनियनों,उद्योग जगत और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विश्लेषकों में भी हलचल पैदा कर दी है।केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा कि जिस उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वह अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। यह कथन अपने आप में दोहरे अर्थों से भरा है।मैंएडवोकेट किशन सम्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि एक तरफ यह स्वीकारोक्ति है कि राष्ट्रीयकरण की मूल भावना, ग्रामीण ऋण पहुंच, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता,अब भी अधूरी है।वहीं दूसरी ओर, यह भी संकेत देता है कि सरकार इसअधूरेपनको पूरा करने के लिए नई नीतिगत दिशा में सोच रही है।बयान के तुरंत बाद मीडिया और बैंकिंग हलकों में सवाल उठा,क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार अब निजीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर रही है? या यह केवल रणनीतिक 'रीपोजिशनिंग' है, जिसमें सरकार अपने कदमों को अधिक राजनीतिक और सामाजिक स्वीकार्यता दिलाने का प्रयास कर रही है? साथियों बात अगर हम 4 नवंबर 2025, को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हीरक जयंती व्याख्यान में वित्तमंत्री का आर्थिक दृष्टिकोण को समझने की करें तो, दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आयोजित हीरक जयंती समापन व्याख्यान (4 नवंबर 2025) में वित्तमंत्री ने जिस स्पष्टता से निजी बैंकों के प्रदर्शन की सराहना की,वह संदेश सीधा था,सरकार निजी क्षेत्र की कार्यक्षमता को स्वीकार कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी बैंक बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं और उनकी गवर्नेंस, कर्ज प्रबंधनऔर टेक्नोलॉजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारी बैंकों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है।इस वक्तव्य को विशेषज्ञों ने एक सॉफ्ट सिग्नल के रूप में देखा है,यह संकेत कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी उसी दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक भावना में लाना चाहती है, जो निजी क्षेत्र में दिखाई देती है। हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी जोड़ा कि राष्ट्रीयकरण का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, जो यह बताता है कि सरकार सामाजिक दायित्वों को नजर अंदाज नहीं कर रही।फिर भी, यह स्पष्ट था कि सरकार अब बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के अंतिम चरण में प्रवेश करने जा रही है और इनमें निजीकरण एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। साथियों बात अगर हम एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स सम्मेलनमें वित्त मंत्री के दूसरे संकेत को समझने की करें तो,12 वें 'एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स सम्मेलन 2025' में वित्त मंत्री ने वित्तीय संस्थानों से उद्योग जगत के लिए कर्ज प्रवाह को बढ़ाने और व्यापक बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विकास के अगले दशक में बैंकों को उद्योगों, स्टार्टअप्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अधिक ऋण देना होगा, ताकि भारत वैश्विक निवेश केंद्र बन सके।यह बयान सिर्फ आर्थिक प्रोत्साहन का आग्रह नहीं था, बल्कि यह एक नीतिगत संकेत भी था,सरकार बैंकिंग प्रणाली को प्रतिस्पर्धी और नवाचार आधारित बनाना चाहती है। निजी क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली पहले से ही इस दिशा में अग्रणी मानी जाती है,फिनटेक, डिजिटल पेमेंट्स,माइक्रो-लेंडिंग और ग्राहक अनुभव के क्षेत्र में। ऐसे में वित्तमंत्री के शब्दों में निजीकरण का समर्थन झलकनास्वाभाविक था।विश्लेषकों का मानना है कि यह भारत सरकार का मिश्रित मॉडल की ओर झुकाव दर्शाता है—जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सामाजिक जिम्मेदारी निभाते रहें, और निजी बैंक आर्थिक गतिशीलता को आगे बढ़ाएं। साथियों बात अगर हम इस बात को समझने की करें कि क्या वास्तव में निजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है? यही सवाल का मूल यही है। क्या सरकार ने बैंक निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है या यह केवल संकेतों की राजनीति है? वास्तविक स्थिति यह है कि 2021 में वित्त मंत्री ने बजट भाषण में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी, जिसे वित्तीय क्षेत्र सुधार का हिस्सा बताया गया था। हालांकि तब से अब तक इस दिशा में कोई औपचारिक अधिसूचना या बिक्री प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। नीति आयोग ने जिन दो बैंकों का चयन किया था उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए, पर चर्चा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम रहे।2023- 24 में सरकार ने इन बैंकों के प्रदर्शन को सुधारने पर अधिक ध्यान दिया,नॉन परफॉर्मिंगएसेट्स कम करने और पूंजी निवेश बढ़ाने की कोशिश की। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार पहले बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत करना चाहती है ताकिनिजीकरण से पहले उन्हें बाजार में बेहतर मूल्यांकन मिल सके।वित्त मंत्री के हालिया बयान कि राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य अभी अधूरा हैको इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार पीछे हटी है, बल्कि यह कि सरकार निजीकरण को धीरे और रणनीतिक तरीके से लागू करना चाहती है, ताकि न तोराजनीतिक विरोध बढ़े और न ही वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो। अर्थात, निजीकरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुई है, पर उसकी तैयारी और माहौल निर्माण स्पष्ट रूप से जारी है। साथियों बात अगर हम बैंक यूनियनों की प्रतिक्रियान्तरफदारी वाले बयान से असहजता को समझने की करें तो वित्तमंत्री के इन बयानों ने जहां उद्योग जगत और निजी क्षेत्र में उत्साह बढ़ाया, वहीं बैंक कर्मचारियों और यूनियनों में चिंता की लहर दौड़ गई। ऑल इंडिया बैंक इम्प्लॉइज एसोसिएशन, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जैसी संस्थाओं ने बयान कोनिजीकरण समर्थक झुकाव बताया।उनका तर्क है कि निजी बैंकों में लाभ प्राथमिक उद्देश्य होता है,जबकि सरकारी बैंकों की भूमिका सामाजिक जिम्मेदारी निभाना है, गांवों में शाखाएं खोलना, गरीबों को सस्ती दर पर ऋण देना, और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। यूनियनों का कहना है कि अगर सरकार निजीकरण की ओर बढ़ती है तो ये सामाजिक लक्ष्य पीछे छूट सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारी वर्ग की नौकरी की सुरक्षा, पेंशन, और ट्रांसफर नीतियों को लेकर भी आशंकाएं हैं। यूनियनों ने 2024 में इस विषय पर देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सरकार ने निजीकरण पर बयानबाजी को सीमित रखा था। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या निजीकरण हमेशा लाभदायक रहा है? को समझने की करें तो,वित्तीय सुधारों का वैश्विक अनुभव बताता है कि बैंकिंग क्षेत्र में निजीकरण का प्रभाव मिश्रित रहा है। ब्रिटेन में 1980 के दशक में बैंकिंग निजीकरण से कार्यकुशलता तो बढ़ी, परंतु ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सीमित हो गई।रूस और लैटिन अमेरिकी देशों में निजीकरण के बाद वित्तीय संकट और सामाजिक असमानता बढ़ी।वहीं सिंगापुर और दक्षिण कोरिया नेहाइब्रिड मॉडल अपनाया,जिसमें सार्वजनिक और निजी बैंक दोनों को समान नीति- आधारित स्वायत्तता दी गई और ये देश वित्तीय स्थिरता के उदाहरण बने।भारत इस समय इन अनुभवों के बीच संतुलन खोज रहा है। पूरी तरह निजीकरण करने से पहले उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय समावेशन, रोजगार सुरक्षा और सामाजिक न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि वित्त मंत्री के हालिया बयानों को अगर शब्दशः देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने निजीकरण से पीछे हटने की घोषणा नहीं की, बल्कि नीति को नए ढंग से प्रस्तुत करने की रणनीति अपनाई है।बैंकिंग क्षेत्र में सुधार अब केवल स्वामित्व परिवर्तन का विषय नहीं रहा, बल्कि यह प्रदर्शन, पारदर्शिता प्रौद्योगिकी और उत्तरदायित्व का समग्र कार्यक्रम बन चुका है। सरकार चाहती है कि जब निजीकरण की औपचारिक घोषणा हो, तब तक बैंकों की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत हो कि कोई भी बिक्री बचाव का उपाय नहीं बल्कि नीतिगत सुधार प्रतीत हो।इसलिए यह कहना उचित होगा कि बैंक निजीकरण की प्रक्रिया अभी औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके संकेत, दिशा और नीतिगत तैयारी स्पष्ट रूप से प्रगति पर हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साय पैसलमण्डा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

पेंशन नियमों में बदलाव से पेंशनर्स खफा

मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद की मासिक बैठक पेंन्शनर्स कक्ष कोषागार कार्यालय परिसर मुरादाबाद के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में पेंशनर्स ने समस्याएं उठाते हुए उनके निराकरण की मांग उठाई। बैठक में सभी सदस्यों द्वारा एक मत होकर कहा कि सरकार पेन्शनरों के प्रति सकरात्मक नही है भारत सरकार/ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 65, 70, 75, एवं 80 वर्ष पर क्रमशः 5, 10, 15 एवं 20 प्रतिशत वृद्धि करने सम्बन्धी ज्ञापन पर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है इसके अतिरिक्त अन्य रा'यों की तरह पेंशनरों /वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में छूट प्रदान नही किया जाना भी पेंशनरों को अनदेखा किया जा रहा

बैठक में पेंशनर्स ने उठाईं समस्याएं

है। परिषद मांग करती है कि उनके द्वारा ज्ञापनों में दिये गये बिन्दुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर तत्काल निर्णय लेकर पेंशनरों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। परिषद की सदस्य मालती देवी ने उन्हे एपीसी का लाभ विभाग द्वारा अभी तक नही दिया गया है, मुद्दा उठाया गया जिसके सम्बन्ध में संगठन द्वारा दो बार संबंधित लिपिक से मिलने का प्रयास किया गया सम्पर्क नही हो सका है प्रयास जारी है । बैठक में अध्यक्ष द्वारा परिषद् के सदस्यों को अवगत कराया गया कि गलती से बढ़ी पेंशन में बिना मंजूरी कटोती नही केन्द्र

सरकार ने इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए यह आदेश पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने हाल में जारी किया है। एक बार तय की गई पेंशन या पारिवारिक पेंशन को घटाया नही जा सकेगा। पेंशन निर्धारण में त्रुटि दो साल से अधिक समय बाद पाई जाती है तो उसे घटाने से पहले सम्बन्धित मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी।

वित्त मन्त्री से 8 वें वेतन आयोग की सन्दर्भ की शर्तों से संशोधन की मांग की जा रही है सभी 8 वें वेतन आयोग की भ्रामक शब्दावली से पेंशनर्स उलझ गये है। वेतन आयोग की शर्तों में पेंशनर्स का कोई उल्लेख नही है ऐसे में पेशनरों को वेतन आयोग के लाभ से वंचित होने का खतरा सता रहा है। अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सक्सेना द्वारा बैठक बताया कि उमंग एप का उपयोग कर घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र बना सकते है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से उमंग एप डाउन लोड करना होगा । जीवन प्रमाण सेवा खोजनी होगी फिर आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर का उपयोग कर बायोमिट्रक या अधार फेस आर्थेटिकेशन के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण करना होगी। अन्य बिन्दुओं के साथ सदस्यों द्वारा आये विचारों पर अध्यक्ष द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निस्तारण का आश्वासन दिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रेम प्रकाश सक्सेना अध्यक्ष एवं संचालन धन सिंह कोषाध्यक्ष द्वारा किया गया। बैठक में दिनेश कुमार शर्मा, सुरभि मिश्रा, आशा रानी, मालती देवी, प्रमोद सक्सेना, अजब सिंह चौह्वन, राम प्रसाद सिंह, रूप किशोर, आशा रानी, पीएस गिल, राम रतन, राशिद अली, अजय बीर सिंह, शैलेश त्यागी, मौ. नईम सिद्दीकी, कल्लू सिंह, केके सिंह, मोहन लाल शर्मा, कंचन कुमार जयानन्द सुयाल, रोहताश त्यागी आदि उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों पर कार्रवाई की उठाई मांग

मुरादाबाद। खिदमते जिंदगी फाउंडेशन हिन्दुस्तान ने सोमवार को यूट्यूबर महक परी, उस्मान भारती और अजीजा के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों का आरोप है कि ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट बनाकर समाज में गंदगी और अश्लीलता फैला रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि अश्लील वीडियो और कंटेंट बनाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराए जाएं ताकि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग सके। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे कंटेंट से युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और समाज में नैतिक गिरावट देखने को मिल रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

टीएमयू की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्मार्ट में जुटेंगे दुनिया के आईटी एक्सपर्ट्स

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद का कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज़ एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी-सीसीएसआईटी फिर इतिहास रचने जा रहा है। 14वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत समेत उज़्बेकिस्तान, आयरलैंड, यूएसए, कतर, सऊदी अरब, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया, एलजीरिया आदि 10 देशों के आईटी विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के 10 तकनीकी सत्रों के 10 ट्रैक में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत 10 सूबों के शोधार्थी अपने-अपने रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत करेंगे। उल्लेखनीय है, 2012 से टीएमयू के सीसीएसआईटी और आईईईई यूपी अनुभाग साझा रूप से हर साल सिस्टम मॉडलिंग एंड एडवांसमेंट इन रिसर्च ट्रेंड्स-स्मार्ट का भव्य आयोजन होता है। स्मार्ट का मुख्य उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, आईओटी और वायरलेस संचार, संचार और

दो दिनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्मार्ट-2025 का शंखनाद 14 नवंबर से

नेटवर्क प्रसारण, सिग्नल इमेज और संचार प्रौद्योगिकी, शासन, जोखिम और अनुपालन, ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी, उद्योग 4.0, एजुकेशन 4.0, सिस्टम मॉडलिंग और डिज़ाइन कार्यान्वयन, रोबोटिक्स, नियंत्रण, इंस्ट्रूमेंटेशन और स्वचालन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकियां, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और सूचना सुरक्षा और इंजीनियरिंग जैसे 1× विषयों पर मंथन करना है। इन विषयों पर देश-दुनिया के जाने-माने एक्सपर्ट्स 97 शोधपत्र प्रस्तुत करेंगे। टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन, जीवीसी मनीष जैन, कार्यकारी निदेशक अक्षत जैन, वीसी प्रो. वीके जैन और डीन एकेडमिक्स प्रो. मंजुला जैन कहते हैं, सीसीएसआईटी स्मार्ट कॉन्फ्रेंस की अब देश और दुनिया में पहचान है। कुलाधिपति सुरेश जैन ने उम्मीद जताई, स्मार्ट टीएमयू के रिसर्चर्स समेत वैश्विक पटल पर मील का

पत्थर साबित होगी। कॉन्फ्रेंस जनरल चेयर और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के डीन प्रो. राकेश कुमार द्विवेदी ने यह जानकारी साझा करते हुए बताया, प्रतीक्षित एवम् प्रतिष्ठित दो दिनी इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ 14 नवंबर से होगा।

तकनीकी सत्रों के अलावा स्मार्ट 2025 कॉन्फ्रेंस में उद्योग और शिक्षा जगत के प्रमुख शिक्षाविदों- एबीवी-आईआईआईटीएम, ग्वालियर के निदेशक प्रो. एसएन सिंह, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, हरियाणा के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार, आईआईटी रुड़की के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. अरुण के. सराफ, एनएसयूटी की प्रोफेसर प्रो. प्रेरणा गौर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रो. मोहम्मद रिहान, ईसीई डेनवर यूनिवर्सिटी, डेनवर के जीएओ प्रो. डेविड वेनज़ोंग, अनुसंधान और विकास एचबीटीयू, कानपुर के डीन प्रो. रघुराज सिंह, वीएसटी यूनिवर्सिटी, रूस के डॉ. डेनिला पैरीगिन, गूगल सर्च, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर तपिश प्रताप सिंह, अमेज़न के सॉफ्टवेयर डवलपमेंट इंजीनियर श्री स्पर्श जैन, ट्युक्सबरी, एमए-यूएसए के नीरज के. द्विवेदी, आरडब्ल्यूटीएच आकिन यूनिवर्सिटी, जर्मनी के रिसर्च एसोसिएट फेलो आईएसीएम डॉ. सत्यवीर सिंह, आरईसी बिजनौर के निदेशक डॉ. नीलेंद्र बादल, आईईटी जीएलए यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शैक्षणिक सहयोग के डीन प्रो. दिलीप के. शर्मा, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा में आईटी के विभागाध्यक्ष डॉ. विभाष यादव, एसएमवीडीयू, कटरा के डॉ. मनोज के. गुप्ता, शिव नादर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, गौतमबुद्ध नगर के डॉ. अंकित गुप्ता, कैपजेमिनी कंसल्टिंग, मैकलीन, वीए, यूएसए के पंकज केआर द्विवेदी, डब्ल्यूआईटी देहरादून के इलेक्ट्रिकल विभाग के एचओडी केसी मिश्रा, जेएनयू, नई दिल्ली के डॉ. करण सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान विभाग की डॉ. विनीता जैन, एमएनएनआईटी प्रयागराज के डॉ. सुमित तिवारी, बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की डॉ. दीपिका पंतोला आदि बतौर कीनोट एड्रैस भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

आमंत्रण / Invitation

मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन (पंजी.)

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025

के शुभ अवसर पर आयोजित समारोह में आप सादर आमंत्रित हैं

दिनांक: 16 नवम्बर 2025 (रविवार) समय: प्रातः 10:00 बजे से

स्थान: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रायसीना रोड, नई दिल्ली

आइए, स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की भावना को नमन करें और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के योगदान का उत्सव मनाएँ।

कार्यक्रम में प्रतिष्ठित मीडिया हस्तियाँ एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे।

AJA Accredited Journalists Association (Regd.)

Press Club of India

आयोजक: मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन (पंजी.) एवं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया

अजय जैन ने चाँदनी चौक वार्ड से भरा नामांकन

नई दिल्ली द्य (साहिल गौड़) दिल्लीनगर निगम के आगामी उपचुनाव में ऐतिहासिक चाँदनी चौक वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी युवा और ऊर्जावान नेता अजय जैन ने सोमवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया।

नामांकन से पूर्व अजय जैन ने अपने निवास पर माँ श्रीमती कंचन जैन से तिलक और मुंह मीठा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने जैन लाल मंदिर और गौरी शंकर मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रैली के रूप में नामांकन स्थल पहुँचे।

इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुदित अग्रवाल, दिल्ली कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के प्रभारी राहुल शर्मा, पूर्व पार्षद अशोक जैन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान, ब्लॉक अध्यक्ष राहुल डाबला, मंडल अध्यक्ष के.एस. राजन, समाजसेवी मनोज गुप्ता, सत्येंद्र जैन सहित चाँदनी चौक के प्रमुख व्यापारी, धार्मिक, सामाजिक संगठनों और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) से जुड़े सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

चाँदनी चौक में जन्मे और पले-बढ़े अजय जैन इस क्षेत्र के एक लोकप्रिय और सक्रिय नेता हैं। वे पूर्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

अजय जैन ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनका उद्देश्य "नया चाँदनी चौक" बनाना है – ऐसा क्षेत्र जहाँ गंदगी, जाम और टूटी सड़कों से मुक्ति मिले। उनका संकल्प है कि क्षेत्र में साफ-सुथरी सड़कों, बेहतर सीवरेज सिस्टम, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, यातायात प्रबंधन और सुंदर विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा, "मेरा सपना है कि चाँदनी चौक की पहचान केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गरिमा के साथ बनी रहे।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर दिनदहाड़े गोली मारकर व्यक्ति ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार, 10 नवंबर को एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर सोमवार को एक व्यक्ति ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें गोली लगने से घायल व्यक्ति का शव मिला। उस व्यक्ति ने सुबह करीब 9:00 बजे दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए मेटल डिटेक्टर गेट के पास स्थित एक चाय की दुकान के पास आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं और घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है और कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारी ने आगे कहा, जिन परिस्थितियों में व्यक्ति ने खुद को गोली मारी, उनकी पुष्टि की जा रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है। दिल्ली की एक अन्य दर्दनाक घटना में मणिपुर की 23 वर्षीय एक महिला की दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर स्थित अपने घर में बिजली की रॉड से पानी गर्म करते समय करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को बताया कि इस घटना के संबंध में रविवार रात आठ बजकर 19 मिनट पर सूचना मिली थी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और देखा कि महिला अपने बाथरूम में बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ में बिजली की एक रॉड थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ''प्रारंभिक जांच से पता चला है कि महिला नहाने गई थी और पानी गर्म करने के लिए बिजली की रॉड का इस्तेमाल कर रही थी। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आई तो उसी इमारत में रहने वाली उसकी दोस्त उसे देखने गई और दरवाजा अंदर से बंद पाया। इसके बाद उसने पुलिस को फोन किया।'' पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल के शवगृह ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि यह बिजली का करंट लगने का मामला प्रतीत होता है और अभी तक किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं है।23 वर्षीय एक महिला की दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर स्थित अपने घर में बिजली की रॉड से पानी गर्म करते समय करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को बताया कि इस घटना के संबंध में रविवार रात आठ बजकर 19 मिनट पर सूचना मिली थी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और देखा कि महिला अपने बाथरूम में बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ में बिजली की एक रॉड थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ''प्रारंभिक जांच से पता चला है कि महिला नहाने गई थी और पानी गर्म करने के लिए बिजली की रॉड का इस्तेमाल कर रही थी।

बिहार चुनाव का दूसरा चरण छोटे दलों की होगी परीक्षा

बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 3.7 करोड़ मतदाता 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। यह चरण, विशेषकर सीमांचल क्षेत्र में, जहां अल्पसंख्यक आबादी का घनत्व अधिक है, महागठबंधन और राजग दोनों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। व्यापक सुरक्षा इंतजामों के बीच कई दिग्गज नेताओं और दलबदलुओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, जो इस चुनावी महासमर को और भी रोचक बना रहा है।

दूसरे चरण में एनडीए-महागठबंधन का सियासी संग्राम

पटना।

बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए रविवार को प्रचार समाप्त होने के बाद, सभी की निगाहें मंगलवार(आज) पर टिकी हैं, जब 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लगभग 3.7 करोड़ मतदाता, जिनमें लगभग 1.95 करोड़ पुरुष और 1.74 करोड़ महिलाएं हैं, मतदान के पात्र हैं। दूसरे चरण में 136 महिलाओं सहित 1,302 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने 45,399 मतदान केंद्र बनाए हैं और हजारों सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। इसने पूरे राज्य में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 500 से अधिक कंपनियों को तैनात किया है। दूसरे चरण में जिन जिलों में मतदान होना है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं, ये सभी नेपाल की सीमा से सटे हुए जिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर पूरे राज्य में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी चुनाव ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। अधिकतर जिले सीमांचल क्षेत्र में आते हैं, जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व अधिक है। ऐसे में यह चरण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। एक ओर महागठबंधन अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन पर भरोसा कर रहा है, वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) विपक्ष पर घुसपैठियों की रक्षा का आरोप लगा रहा है। प्रमुख उम्मीदवारों में जनता दल (यू) के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य बिजेंद्र प्रसाद यादव शामिल हैं, जो सुपौल सीट से लगातार आठवीं बार जीत दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं।

तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप; भाजपा शासित प्रदेशों से ही सुरक्षा बल क्यों बुलाई गई

पटना । पटना के पोलो रोड में दूसरे चरण के मतदान से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ सांसद मीसा भारती भी मौजूद रहीं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनाव में भाजपा शासित प्रदेशों से ही सुरक्षा बल क्यों बुलाई गई। 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्य की लगाई गई है। 68त्र पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से है। तेजस्वी ने सवाल पूछा कि बंगाल तमिलनाडु झारखंड की पुलिस क्यों नहीं मंगवाई गई।

पीएम ने बाहुबलियों के लिए प्रचार किया

तेजस्वी यादव ने कहा कि, हमलोग विकास की बात कर रहे हैं। पीएम कट्टे की। पता नहीं वो कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं। पीएम ने आपराधिक छवि के लोगों के साथ मंच साझा किया। सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी विपिन शर्मा से एयरपोर्ट पर मिले और पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री ने अनंत सिंह, हुलास पांडेय जैसे बाहुबलियों के लिए भी प्रचार किया।

जनता बदलाव के मूड में है

तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने सबसे अधिक 171 सभाएं की है। कोई ऐसा जिला, ब्लॉक नहीं बचा जहां हम नहीं गए। लोगों का मूड बदलाव का है। 20 साल पुरानी सरकार को बदलना है। 20 साल राज करने के बाद भी एनडीए सरकार ने बिहार को सबसे पीछे किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि, बिहार के लोग इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमने सदन में पूछा कि, बिहार किस चीज में आगे है। वो बता दो। दोनों में से कोई नहीं बता पाया। 14 तारीख को हमारी सरकार बनेगी। आने वाले दिनों में बिहार आगे बढ़ेगा।

तेजस्वी यादव के वादों की झड़ी

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में 30 हजार रुपये भेजे जाएंगे। साथ ही जीविका दीदीयों का ब्याज माफ किया जाएगा और उन्हें 30 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। तेजस्वी ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, किसानों के लिए फ्री बिजली, और 'बेटी योजना' व 'मां योजना' शुरू करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में हर घर को सरकारी नौकरी देने की दिशा में काम किया जाएगा। कानून-व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए तेजस्वी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका दावा है कि 14 नवंबर को परिणाम आने के बाद 18 नवंबर को शपथ लेकर 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच सभी अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दीपावली पर सिलेंडर फ्री करने की गारंटी कहां गई? अब बिहार की जनता झूठे वादों में नहीं फंसने वाली है।

समस्तीपुर में पर्चियां मिलने का भी जिक्र

हम चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। समस्तीपुर में पर्चियां फेंकी मिली थी। लोग डरे हुए हैं। घबराए हुए हैं। गृहमंत्री को कोई काम नहीं पटना में डेरा बनाए हुए हैं। कई बड़े-बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, निर्देश दिए गए हैं। कहां गड़बड़ी करनी है। चुनाव से पहले किन-किन लोगों को उठाना है। ये बताया जा रहा है।

ये बौखलाहट बता रही है कि ये लोग जाने वाले हैं। हम लोगों की पैनी नजर है। ये सूचना हमें उन्हीं अधिकारियों से मिली है, जिन्हें ये निर्देश दिए गए हैं। 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने पहले फेज में कितने महिला और पुरुष मतदाताओं ने वोटिंग की इसका आंकड़ा नहीं दिया है। ये क्यों छिपाया जा रहा है।

एसआईआर को ममता ने बताया सुपर इमरजेंसी बोलीं- मेरा गला काट दो पर मतदाता न हटाओ

बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रोकने की माँग की है और इसे सुपर इमरजेंसी बताया है। उत्तर बंगाल में एक प्रशासनिक बैठक में बोलते हुए, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर चुनाव अधिकारियों को व्यस्त रखने का आरोप लगाया ताकि सरकार अगले तीन महीनों तक ठीक से काम न कर सके। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी जानी चाहिए।

ममता बनर्जी ने कहा कि यह लोगों को बदनाम करने की जानबूझकर की गई कोशिश है! इतने लोग मारे गए, चुनाव आयोग ने एक भी शोक संदेश नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, आप मुझे जेल भेज सकते हैं या मेरा गला काट सकते हैं, लेकिन एक भी असली मतदाता का नाम मत काटो। बनर्जी ने चुनाव से पहले एसआईआर कराने की जरूरत पर संदेह जताया और इसे वोटबंदी की कवायद बताया। उन्होंने भारत की सुरक्षा स्थिति और कथित घुसपैठ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला और कहा कि आंतरिक सुरक्षा, सीआरपीएफ और बीएसएफ उनके अधीन आते हैं और उनके इस्तीफे की मांग की। मुख्यमंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की भी आलोचना की और इसे एक बड़ी भूल बताया जिसे वापस लिया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और जोर देकर कहा कि अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूट गया= तो केंद्र की भाजपा सरकार का गिरना तय है। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर भाजपा का राजनीतिक हथियार होने का आरोप लगाया और कहा कि यह संशोधन अभियान चुनिंदा और दुर्भावनापूर्ण इरादे से चलाया जा रहा है। उन्होंने एसआईआर को विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से जोड़ते हुए कहा कि यह वैध मतदाताओं को डराने और उनके मताधिकार से वंचित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है।

जम्मू कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

दो डॉक्टर समेत सात गिरफ्तार, 2,900 किलो विस्फोटक और हथियार बरामद

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़ा हुआ था। इस सफलता से कई प्रमुख आतंकी आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

पुलिस के अनुसार, 19 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के बुनपोरा, नौगाम में कई जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें पुलिस और सुरक्षाबलों को धमकाया गया था। इसके बाद एफआईआर संख्या 162/2025 दर्ज की गई और जांच शुरू हुई। जांच में यह सामने आया कि यह नेटवर्क शिक्षित और पेशेवर युवाओं से जुड़ा था और विदेशी संपर्कों के माध्यम से संचालित हो रहा था। जांच में पता चला कि यह समूह एन्क्रिप्टेड चैनलों के जरिए भर्ती, समन्वय, धन-संग्रह और लॉजिस्टिक्स का काम करता था। धनराशि पेशेवर और शैक्षणिक नेटवर्क के माध्यम से, सामाजिक या धर्मार्थ कारणों का बहाना बनाकर जुटाई जा रही थी। आरोपी आतंकवाद के लिए लोगों की पहचान कर, उन्हें कट्टर बनाने और हथियार/आईईडी बनाने के लिए सामग्री जुटाने के लिए काम करता था ।

आतंकी मुजम्मिल के करीबी इमाम के घर से बरामद हुए विस्फोटकों के 50 बोरे

फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम को विस्फोटक पदार्थ के 50 बोरे और मिले है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि पुलिस इन बोरों को पिकअप गाड़ी में भरकर ले जा रही है। यह बोरे आतंकी मुजम्मिल के करीबी इमाम के घर से बरामद किए गए है। इन बोरे में क्या विस्फोटक पदार्थ है? इसको लेकर पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। बताया गया कि जिस घर से ये सामान बरामद हुआ है, वो घर गांव के ही रहने वाले इमाम का है। इसके पास मुजम्मिल अक्सर मिलने के लिए आता जाता रहता था। फतेहपुर तगा से पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान 2563 किलोग्राम विस्फोटक मिला है। इस विस्फोटक को 50 बोरों में भरकर रखा गया था। पुलिस टीम को जिस मकान से ये विस्फोटक मिला है। वह मस्जिद के इमाम इश्तियाक का था। उसने यह मकान चार साल पहले खरीदा था। यह मकान उसने किसी परिवार को किराए पर दिया हुआ है।

केरल में स्थानीय निकाय चुनाव का शंखनाद, दो चरणों में 9 और 11 दिसंबर को वोटिंग

नई दिल्ली । केरल राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव नौ और 11 दिसंबर को दो चरणों में होंगे। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, कोट्टायम, अलप्पुझा, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में मतदान नौ दिसंबर को होगा। त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, वायनाड, कोझीकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के मतदाता 11 दिसंबर को वोट डालेंगे।

यूपी के स्कूलों में वंदे मातरम होगा अनिवार्य, झूठ और इमोशंस पर चल रही सरकार- अखिलेश यादव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को सभी स्कूलों राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान किया है. गोरखपुर के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि प्रदेश की सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अनिवार्य करेंगे. योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय पर यूपी के पूर्व सीएम व सपा चीफ अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है. अखिलेश यादव ने वंदे मातरम को अनिवार्य किये जाने पर कहा, हम जनगण मन सुनेंगे... अभी एक बच्चा आया था मैं उसे मिठाई देना चाहता था लेकिन उसने कहा मुझे केक चाहिये, मैं क्या जबरदस्ती उसके मुंह में लड्डू डाल दूं? अखिलेश ने कहा एक छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता, हमने देश क्यों आजाद करवाया? क्योंकि हम आजादी चाहते थे, ताकि हमारा अपना संविधान हो. पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि, ये बहस आज हम कर रहे हैं, क्या उस समय जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने बहस नहीं की? इसीलिये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया. अगर यही होता कि इसे गाना ही गाना है तो क्यों अनिवार्य नहीं किया गया? उन्होंने चॉइस छोड़ दी थी. अखिलेश यादव ने कहा कि, भाजपाइयों से कई बार पूछा गया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है तो नहीं जानते थे. भाजपाई राष्ट्रगीत गा नहीं पाए. पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने अखिलेश यादव ने कहा कि स्कूलमें आधार कार्ड नहीं मान रहे है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आधार को मनवाएंगे. सपा चीफ ने कहा कि किसान आज भी परेशान है, खाद कहीं मिलती नहीं. सरकार कहती है खाद उपलब्ध है.

महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश ने सरकार को घेरा

महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि, सोचिए महंगाई इन्होंने कहां पहुंचा दी, गाड़ियां महंगी, घर मकान महंगा, सोना भी महंगा, सोना इकट्ठा कर रही है बीजेपी. सपा चीफ ने कहा, सरकार से अगर हम पूछें कि जो राशन पाने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, तो सरकार आज भी बताने के लिए तैयार नहीं है. पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि यह सरकार झूठ पर चल रही है, इमोशंस पर चल रही है, डराकर सरकार चल रही है. आगे यहा भी कहा, एक भी अधिकारी जो इलेक्शन देखता है उसमें कोई भी पीडीए परिवार का नहीं है.

लाल किले के पास कार में धमाका : 10 की मौत, 24 घायल

दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, यूपी में हाई अलर्ट; शाह अस्पताल पहुंचे

नई दिल्ली।

दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए एक आतंकवादी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट के पीछे किसी आतंकवादी साजिश का संदेह जताया जा रहा है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अभी तक इसे आतंकवादी हमला नहीं माना है। बम विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी गूंज चार किलोमीटर तक सुनाई दी और पास से गुजर रहे छह वाहन इसकी चपेट में आ गए। 20 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुँचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को लोक नायक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ खबर लिखे जाने तक 15लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 24 से ज्यादा घायल हैं। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आतंकवाद निरोधी दस्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) घटना की जाँच कर रहे हैं। विस्फोट शाम करीब 6:50 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर हुआ। घटनास्थल पर, विस्फोट की चपेट में आए वाहनों से आग की लपटें उठने लगीं, जिससे बड़ी संख्या में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि एक कार का एक हिस्सा लाल किले के पास लाल मंदिर पर जा गिरा, जिससे मंदिर और मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए। विस्फोट के तुरंत बाद, आसपास की दुकानों में आग लगने की सूचना मिली। चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस इलाके तक भूकंप का झटका महसूस किया गया और दुकानदार एक-दूसरे को फोन करके स्थिति की जानकारी लेते देखे गए। कई बसों और अन्य वाहनों में भी आग लगने की सूचना मिली है। अग्निशमन विभाग को शाम को कार में विस्फोट की सूचना मिली। इसके बाद, उसने तुरंत छह एम्बुलेंस और सात दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा। राहत और बचाव कार्य जारी है और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। विस्फोट का कारण अभी भी अज्ञात है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और जाँच एजेंसियाँ घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही हैं। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि विस्फोट एक कार में हुआ था, लेकिन इसकी प्रकृति और कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। घटना के बाद, पूरे लाल किला और चांदनी चौक इलाके के साथ-साथ दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह-जगह वाहनों की जाँच की जा रही है। लोक नायक अस्पताल के निदेशक डॉ. बीएल चौधरी ने बताया कि अस्पताल लाए गए एक घायल की बाईं आँख और चेहरा फट गया। प्रत्यक्षदर्शी प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित बलबीर सिंह ने बताया कि वह वैगन-आर कार में बैठे थे और विस्फोट में बाल-बाल बच गए क्योंकि उनका भाई चांदनी चौक से सामान खरीदने गया था। वह उसे लाल किले पर बुला रहे थे, लेकिन वह नहीं गया। वह वहीं इंतजार करता रहा, तभी विस्फोट हो गया। विस्फोट में फंसा एक व्यक्ति उनकी कार पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

सभी संभावनाओं की करेंगे जांच- गृह मंत्री

आज शाम करीब 7 बजे, दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई आई20 कार में धमाका हुआ। इस विस्फोट में कुछ राहगीर घायल हुए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है। विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर, दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गईं। एनएसजी और एनआईए की टीमों ने एफएसएल के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है। आस-पास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं। मैंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी से भी बात की है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी मौके पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच करेंगे। सभी विकल्पों की तुरंत जाँच की जाएगी और हम परिणाम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं शीघ्र ही घटनास्थल पर जाऊँगा और तुरंत अस्पताल भी जाऊंगा।

पीएम मोदी ने भी व्यक्त की संवेदनाएं

पीएम मोदी ने कहा, आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- ये घटना बेहद दर्दनाक

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में कार ब्लास्ट की ये घटना बेहद दर्दनाक और परेशान करने वाली है। इस शोक के पल में, मरने वालों के परिवारों को मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।

पुलिस ने बताया- जिस कार में धमाका हुआ, वह हरियाणा की

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जिस आई 20 कार में धमाका किया गया है। वह गुरुग्राम के एचआर 26 नंबर की है। यह गाड़ी नदीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड होने की सूचना है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया है।